'पोत निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण' के ऊपर फिक्की अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान एडमिरल करमबीर सिंह, नौसेनाध्यक्ष का संबोधन – 25 जुलाई 2019

वहाँ दिया गया भाषण इस प्रकार से है:

मुझे 'पोत निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण ' जैसे बहुत ही सामयिक मुद्दे के ऊपर इस सेमिनार का संबोधन करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज इस हॉल के अंदर एकत्र समुद्री विषयों के बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत करना भी सौभाग्य की बात है।

मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इस सेमिनार की मेजबानी करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ; साथ ही मैं हमारे नॉलेज पार्टनर नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन; समुद्री समुदाय से आए विशिष्ट दर्शकों; उद्योग, अकादमिक और सरकारी संगठनों, साथ ही सभी प्रतिभागियों का इस सेमिनार को समर्थन देने के लिए भी धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि यह कार्यवाही उन विचारों के लिए एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगी जिन्हें भारत में पोत–निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा सकता है।

सरकार ने वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की योजनाओं की घोषणा की है। मेरे विचार से पोत–निर्माण का क्षेत्र इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मुझे यकीन है आज अनेक वक्ता पोत–निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उपायों पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से भारत में पोत के कमर्शियल निर्माण के ऊपर। हालाँकि, मैं भारतीय नौसेना के पोत निर्माण से जुड़े कदमों और राष्ट्र निर्माण के प्रति इसकी सहलग्नता पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, 'मेक इन इंडिया' के एक राष्ट्रीय मिशन बनने से 50 वर्ष पहले से ही भारतीय नौसेना देश में पोत–निर्माण परितंत्र को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, वर्ष 1964 में घरेलू 'सेंट्रल डिज़ाइन ऑफिस' के निर्माण के माध्यम से नौसेना ने देश में पोत–निर्माण की दिशा में रचनात्मक कदम उठाए। आज तक, नौसेना ने 19 विभिन्न वर्गों में 90 से भी अधिक युद्धपोतों को डिज़ाइन किया है। वर्ष 1961 में जीआरएसई द्वारा निर्मित पहली पोत भा नौ पो अजय के बाद भारतीय शिपयार्ड्स में 130 से भी अधिक मंचों के निर्माण के साथ, नौसेना पोत–निर्माण को भारत की सफल कहानियों में से एक गिना जा सकता है। यह प्रमाण है नौसेना और उद्योग के बीच तालमेल का, साथ ही आत्म–निर्भरता की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का भी।

फिर भी, हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि 'खरीदार नौसेना' से 'निर्माता नौसेना' तक का यह सफ़र कठिन रहा है। आज, जबकि नौसेना 'फ्लोट', 'मूव' और 'फाइट' वर्गों के भीतर पोत–निर्माण और उपकरणों के एक सम्मानजनक प्रतिशत का दावा करती है, हमें भविष्य की चुनौतियों की पूर्ण जानकारी है। आज के वित्तीय माहौल में हमें हर रुपया विवेक से और स्थिति अनुसार उचित उपयोग के लिए खर्च करना है। पोत निर्माण में अधिक समय और लागत से बजट प्रबंधन में चुनौतियां पैदा हो जाती हैं। साथ ही, पोत–निर्माण के अधिक पूंजी वाली गतिविधि होने के नाते आमतौर पर समझा जाता है कि नौसेना पोत–निर्माण के लिए बजट आवंटन अर्थव्यवस्था पर बोझ होता है।

तब भी, मैं कहना चाहूँगा कि नौसेना पोत–निर्माण में निवेश से अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं पड़ता है। मैं कुछ मिनट लेते हुए इस बात को समझाने के लिए 3 कारणों का उल्लेख करूंगा कि जिसे हम कभी–कभी 'बोझ' या फिर 'डूबी हुई लागत' समझते हैं वो दरअसल ऐसी नहीं है और नौसेना पोत–निर्माण वास्तव में आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में बढ़िया योगदान करता है।

पहला कारण है ' प्लो–बैक ' *प्रभाव*।

पारंपरिक अनुमानों के अनुसार, नौसेना पर खर्च किए गए हर रुपए का एक बड़ा अनुपात भारतीय अर्थव्यवस्था में वापस लौट आता है। सबसे पहले तो, नौसेना बजट का 60% से भी अधिक पूंजीगत व्यय को समर्पित होता है। इस पूंजी बजट का लगभग 70% घरेलू सोर्सिंग पर खर्च किया जाता है, जो पिछले पांच वर्षों में लगभग 66,000 करोड़ रुपए है। 2014 में 'मेक इन इंडिया' की शुरुआत से ही, लागत के आधार पर 80% एओएन भारतीय विक्रेताओं को प्रदान किए गए हैं। अभी तक विभिन्न शिपयार्ड्स में ऑर्डर किए गए कुल 51 पोतों और पनडुब्बी में से 49 का निर्माण देश में किया जा रहा है। यह बात सिद्ध करती है कि नौसेना पोत–निर्माण से भारी मात्रा में धन अर्थव्यवस्था में वापस लौट कर आता है।

पोत निर्माण की प्रत्येक परियोजना रसद, स्पेयर्स और परियोजना समर्थन परितंत्रों का निर्माण करती है, जिसमें ओईएम, सहायक उद्योग, और प्रत्येक मंच का समर्थन करने के लिए एमएसएमई शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, जीआरएसई के पास चालू नौसेना पोत–निर्माण परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए लगभग 2100 कंपनियां पंजीकृत हैं। मंच या पोत के जीवनकाल के लगभग तीन से भी अधिक दशक के दौरान बाद में पोत की मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता के चलते घरेलू उद्योग में भारी निवेश किया जाता है। भारतीय विक्रेताओं द्वारा पोत की मरम्मत का मूल्य के हिसाब से लगभग 90% कार्य किया जाता है, जिसमें अधिकतर एमएसएमई शामिल होते हैं, जिसका अर्थ है कि पूंजी बजट के अलावा नौसेना के राजस्व का एक बड़ा अनुपात अर्थव्यवस्था में वापस लौट रहा है।

हमारा देश आज रोजगार सृजन और कौशल विकास की चुनौतियों से जूझ रहा है और अपने दूसरे योगदान के रूप में नौसेना पोत–निर्माण एक उत्प्रेरक का कार्य करता है।

एक कहावत है "आदमी को मछली देकर हम उसे एक दिन का भोजन दे सकते हैं; मछली पकड़ना सिखा कर हम उसको आजीवन भोजन दे सकते हैं।" पोत निर्माण एक कुशल गतिविधि है। पोत निर्माण की प्रत्येक परियोजना में रोजगार के अवसर और कार्यबल के कौशल विकास के साथ भारी मात्रा में श्रम शक्ति का निवेश किया जाता है। मंचों के और जटिल बनने के साथ ही, कौशल स्तर में भी उसी अनुपात में उन्नति की जाती है।

नौसेना पोत–निर्माण परियोजनाओं ने रोजगार और कौशल विकास की दिशा में काफी योगदान किया है, जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। अध्ययनों से पता चलता है कि पोत–निर्माण उद्योग उन उद्योगों में से एक है जहाँ सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया जाता है। युद्धपोत निर्माण की जटिलता का तात्पर्य कमर्शियल निर्माण के मुकाबले अधिक श्रमशक्ति अवशोषण भी होता है। उदाहरण के लिए, लगभग 30,000 टन वाले कमर्शियल पोत के निर्माण के लिए नियुक्त कर्मचारियों की संख्या लगभग 6,000 टन वाले युद्धपोत के निर्माण में नियुक्त कर्मचारियों से कम होती है। इसके अलावा, युद्धपोत निर्माण में शामिल जटिलताओं को देखते हुए, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का अनुपात अधिक होता है। इस प्रकार से, विविध शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से हमारे देश के शिक्षित युवाओं को।

इसके अलावा, आँकड़े दिखाते हैं कि एक शिपयार्ड में कार्यरत एक कर्मचारी का मल्टीप्लायर प्रभाव सहायक उद्योगों पर लगभग 6.4 गुणा होता है। उदाहरण के लिए, प्रोजेक्ट 17 ए फ्रिगेट्स में यार्ड के भीतर प्रति वर्ष लगभग 4,500 कर्मचारियों को रोजगार देने की संभावना है, लेकिन सहायक उद्योगों में प्रति वर्ष लगभग 28,000 कर्मचारियों को रोजगार दिया जाएगा।

व्यक्तिगत कौशल के अलावा, नौसेना परियोजनाओं के चलते शिपयार्ड्स के भीतर नई क्षमताओं का भी सृजन होता है। अर्थव्यवस्था के लिए यह महत्वपूर्ण अनपेक्षित लाभ है। उदाहरण के लिए, कोचीन शिपयार्ड में भारत की सबसे बड़ी निर्माणाधीन सूखी गोदी में विमान वाहकों के अलावा बड़े आकार के कमर्शियल पोतों की सर्विसिंग सक्षम हो पाएगी, जो कि इस परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। इसी प्रकार से, आईएसी 1 के लिए घरेलू इस्पात की आवश्यकता के चलते डीएमआरएल, हैदराबाद द्वारा घरेलू रूप से डीएमआर 249 ए इस्पात का निर्माण किया गया है जिसका उपयोग नौसेना की अन्य परियोजनाओं में भी किया जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगभग 50,000 टन घरेलू इस्पात की आपूर्ति की है, जिसे अभी तक आयात किया जाता रहा था। संक्षेप में बताया जाए तो, पोत–निर्माण में मूर्त और अमूर्त दोनों तरीकों से अन्य क्षेत्रों में योगदान करने की क्षमता है।

अंत में, नौसेना पोत–निर्माण परियोजनाएं देश के लिए सामरिक नतीजों में भी योगदान देती हैं।

हम सभी जानते हैं कि हमारे उद्योग द्वारा निर्मित बहु–आयामी, अत्याधुनिक पोत, जिनका संचालन नौसेना और तट रक्षक बल द्वारा किया जाता है, हिंद महासागर के क्षेत्र और उससे आगे भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने में अहम हैं। इसके अलावा नौसेना के राजनैतिक कार्यों और क्षमता निर्माण के प्रयासों के चलते अनेक मित्र राष्ट्रों ने पोत–निर्माण के हमारे कौशल का उपयोग किया है। हमने पहले से ही मित्र राष्ट्रों, जैसे के सेशेल्स, मालदीव और श्रीलंका आदि की समग्र सुरक्षा को बढ़ाने के लिए युद्धपोतों का निर्यात कर उनकी क्षमताओं में वृद्धि की है। भारत के पोत–निर्माण उद्योग के परिपक्व होने के साथ ही, सामरिक भागीदारियों का निर्माण करने और मित्र राष्ट्रों को रक्षा पोत–निर्माण से जुड़े निर्यात और मरम्मत के लिए भारत को सामरिक केंद्र में बदलने की अपार क्षमता है।

हालाँकि, इस प्रकार के सामरिक नतीजों को सक्षम बनाने के लिए, देश को घरेलू पोत–उत्पादन और पोत–मरम्मत क्षमता में निश्चित 'न्यूनतम संसाधन' हासिल करने की आवश्यकता है। जबकि रक्षा पोत–निर्माण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षमताओं को बढ़ाने और वास्तविक सामर्थ्य को हासिल करने के लिए मर्केंटाइल मरीन और तटीय शिपिंग जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध बढ़त का फायदा उठाने की वाकई हमें ज़रूरत है।

अंत में मैं श्रोताओं को घरेलू पोत–निर्माण और क्षमता विकास पर भारतीय नौसेना द्वारा लगातार ध्यान दिए जाने का आश्वासन देना चाहूँगा। सामरिक भागीदारी मॉडल का संचालन करने, बाय एंड मेक (भारतीय) श्रेणी के तहत अनुबंधों को पूरा करने, और मेक–II परियोजना के तहत अनुबंध के प्रोटोटाइप का विकास करने वाली पहली सेना होने के नाते, अधिक आत्म–निर्भरता हेतु हमारे सामूहिक अनुसंधान में उद्योग के साथ भागीदारी करने के प्रति हम वचनबद्ध हैं।

इसके साथ ही, मैं सेमिनार और प्रतिभागियों की सफलता की कामना करता हूँ। सभी हितधारकों की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देख कर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे यकीन है कि यह चर्चाएं देश में पोत–निर्माण के परितंत्र के प्रयासों को मजबूत करेंगी।